

रीवा जिले की अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रभाव

डॉ. बी.बी. व्यौहार

प्राध्यापक, शोध-निर्देशक

अर्थशास्त्र विभाग, ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना (म.प्र.)

कीर्ती सिंह

शोधार्थी, एम.ए. अर्थशास्त्र

ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना (म.प्र.)

सारांश :-

संरचनात्मक आधारभूत परिवर्तन में सहायक आर्थिक विकास के मानक पहलुओं में लघु कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कुटीर उद्योग धन्धे समय अनुकूल सृजित होते हैं, विकसित होते हैं और मांग तथा उपयोगिता अनुकूल परिष्कृत एवं परिवर्धित होते हैं। एक दौर ऐसा था जब मशीनीकरण कम थीं उसकी जगह मानव श्रमशक्ति तथा कारीगरी सूक्ष्म एवं सुदृढ़ वस्तुओं का निर्माण करते थे। समय के साथ आये परिवर्तन ने मानव श्रमशक्ति की जगह मशीनीकरण कर दिया। जिससे वस्तुएं सरलता से कम श्रमशक्ति से और अवशिष्ट पदार्थों से वस्तुओं का निर्माण प्रारंभ कर दिया। मशीनों से बने दैनिक उपभोग की वस्तुओं में मृदा, काष्ठ, एवं धातु की जगह प्लास्टिक तथा मिश्रित अनुपयोगी धातुओं के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने लगे हैं जिसका प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा पड़ा है। कभी स्वावलम्बी रहने वाले ग्राम अब शहरों से आयातित वस्तुओं पर निर्भर होने लगे हैं। आचार्य तब होता है जब ग्राम में सब्जियाँ और दूध उपभोग के लिए पहुँचते हैं। निश्चित ही यह समस्या लघु कुटीर उद्योग धन्धों का पराभव होने से हो रहा है। उक्त बिन्दुओं को इस आलेख में प्रस्तुत करने का प्रयास है।

मुख्य शब्द :- अर्थव्यवस्था, लघु, कुटीर, उद्योगों, उपभोक्ता, प्लास्टिक, मिश्रित, अनुपयोगी, श्रमशक्ति, प्रभाव आदि।

प्रस्तावना -

भारत में प्राचीन काल से ही लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है किन्तु ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान यहाँ का परम्परागत हस्तशिल्प उद्योग बहुत प्रभावित हुआ। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती गई। स्वतंत्रता के बाद लघु और कुटीर उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया क्योंकि ये उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न समस्याओं को हल करने तथा उसके भावी विकास की संभावनाओं का आधार बन सकते हैं। महात्मा गाँधी ने लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व को ध्यान में रखकर ही कहा था कि "भारत का मोक्ष लघु और कुटीर उद्योगों में निहित है।"

समय के साथ आए बदलाव ने लघु उद्योग क्षेत्र को तकनीकी अर्थ में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के रूप में नई पहचान दी है। यह अनुमान किया जाता है कि मूल्य के अर्थ में, यह क्षेत्र निर्माण की दृष्टि से 39 प्रतिशत एवं देश के कुल निर्यात के 33 प्रतिशत हिस्से के लिए जिम्मेदार है। हाल के वर्षों में यह क्षेत्र सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में उच्च विकास दर दर्ज करा रहा है। क्षेत्र का वृहद् लाभ यह है कि "इसकी रोजगार क्षमता न्यूनतम पूँजी लागत पर है। वर्तमान में यह क्षेत्र 12.86 मिलियन माइक्रो और लघु उपक्रमों के जरिये अनुमानतः 31.4 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार देता है और इस क्षेत्र में मजदूरों की तीव्रता वृहद् उद्योगों की तुलना में 4 गुना ज्यादा अनुमानित की गयी है।" इस तरह लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय



अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं—योजना आयोग के अनुसार लघु उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार "लघु उद्योग बड़े पैमाने पर तत्काल रोजगार प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय आय के अपेक्षाकृत अधिक न्यायपूर्ण वितरण का आश्वासन देते हैं और पूँजी तथा कुशलता के साधनों की प्रमाणिक ढंग से गति देते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग के अर्थव्यवस्था में महत्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है— रोजगार में वृद्धि — कृषि के बाद रोजगार और आय प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र लघु और कुटीर उद्योगों का है। लघु क्षेत्र में अर्द्ध- बेरोजगार व्यक्ति को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं इसमें मौसमी बेरोजगार किसान को भी रोजगार प्राप्त होता है। ये उद्योग कम पूँजी में अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने में समर्थ होते हैं। इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएँ भी होती हैं।

लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास से राष्ट्रीय आय का अधिक बेहतर और न्यायोचित वितरण हो सकता है क्योंकि बड़े उद्योगों का विकास आय के वितरण में असमानता को बढ़ाता है, देश की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग मुट्ठीभर पूँजीपतियों की जेबों में चला जाता है। इनके विपरीत लघु उद्योग का स्वामित्व लाखों व्यक्तियों व परिवारों के हाथों में होता है। फलस्वरूप आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण नहीं हो पाता तथा आय के समान वितरण में सहायता मिलती है।

देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल लघु एवं कुटीर उद्योग स्थानीय आवश्यकताओं, संसाधनों और कौशल के प्रयोग की दृष्टि से अधिक उपयुक्त हैं क्योंकि लघु उद्योग हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल है। हमारे देश में पूँजी का अभाव है तथा श्रम का बाहुल्य है। अधिकांश लोग कृषि व्यवसाय में संलग्न है, जो वर्ष में कई महीने खाली रहते हैं। अतः वे अपने खाली समय का सदुपयोग लघु उद्योगों में काम करके कर सकते हैं तथा अपनी आय बढ़ा सकते हैं। दूसरे, कम पूँजी विनियोग से अधिक लोगों को रोजगार देने में ये उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

लघु एवं कुटीर उद्योग भुगतान शेष के संदर्भ में अनुकूल है क्योंकि निर्यात आय में इनका योगदान अधिक होता है तथा आयात पर कम निर्भर होते हैं जबकि बड़े उद्योगों के लिए मशीनें एवं तकनीकी का आयात विदेशों से किया जाता है परन्तु लघु उद्योगों में न तो मशीने आयात करनी पड़ती है और न तकनीकी, अतः आयात पर लघु एवं कुटीर उद्योगों की निर्भरता कम होती है।

बड़े पैमाने के उद्योग मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में स्थापित किये जाते हैं। अतः देश के कुछ भागों का ही विकास हो पाता है। अन्य क्षेत्रों में पिछड़े रह जाते हैं। अतएव पिछड़े हुए भागों के औद्योगिक विकास के लिए लघु उद्योगों का विकास प्रभावी पहल उत्पादन और उत्पादकता के मध्य सेतु रचना के स्रोत हैं।

ये उद्योग देश के संतुलित विकास में सहायक होते हैं और देश के चौमुखी विकास के लिए सहायक होते हैं। न्यून औद्योगिक विवाद व समस्याएँ प्रायः लघु एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र, बड़े उद्योग क्षेत्र की तुलना में अधिक कार्य कुशल और लाभप्रद है तथा यहाँ औद्योगिक विवाद भी न के बराबर है जबकि बड़े उद्योगों में श्रमिकों की हड़तालें, श्रमिकों की छंटनी, मालिकों द्वारा तालाबंदी की समस्याएँ होती हैं। कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता— लघु उद्योगों में पूँजी तो कम लगती ही है, साथ ही साथ तकनीकी ज्ञान की भी कम आवश्यकता होती है। अतः श्रमिकों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती और उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो जाता है।

लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएं उत्तम गुणवत्ता तथा कलात्मक होती हैं। इनमें कारीगरों को अपने हुनर व कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है तथा इनके द्वारा उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्ट किया जा सकता है। निर्माण—उद्योग या



उद्योग कृषि तथा उत्खनन से प्राप्त प्राथमिक उत्पादों (कच्चा माल) को संसाधित करके तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया निर्माण-उद्योग या उद्योग कहलाती है।

अर्थव्यवस्था को आधार भूत बनाने के लिए उद्योगपतियों ने क्रियाशील छोटे उद्योगों के रूप में विनियत किया। उनके अनुसार उद्योगों को वर्गीकृत करते हुए इसे विभाजित किया गया है। (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता के अनुसार लघु उद्योग सबसे ज्यादा योगदान देता है भारत जैसे देश जहाँ बेरोजगारी अधिक है तथा श्रम की उपलब्धता है बदलते समय के साथ समाज की आवश्यकताओं के मुताबिक लघु उद्योग की दिशा व उत्पाद निर्भर करते हैं यह उद्योग मूल रूप से औद्योगिक कौशल पर आधारित है। जिसमें कम पूँजी, थोड़े से प्रशिक्षण और सीमित मात्रा में श्रम के साथ इसे शुरू किया जा सकता है अपने परिवार के सदस्यों की भागीदारी से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। लघु उद्योग के क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों में सही क्षेत्र का चुनाव, कच्चे माल की आपूर्ति, तकनीकी ज्ञान तथा बाजार की उपलब्धता मुख्य है।

लघु उद्योग वे उद्योग है जो विनिर्माण उत्पादन और सेवाओं के प्रतिपादन में छोटे पैमाने पर किए जाते हैं। जिसमें आधुनिक ढंग से उत्पादन कार्य किया जाता है। श्रमिकों का पूँजी निवेश भी होता है। इन उद्योगों में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच सम्बन्ध प्रत्यक्ष और सौहार्दपूर्ण होते हैं। कुटीर उद्योग आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं जो निवास स्थानों में ही स्थापित होते हैं। ये उद्योग बहुत ही कम लागत में चालू किये जा सकते हैं। अतः इन्हें शुरू करने के लिए पैसों की व्यवस्था बड़ी आसानी से की जा सकती है साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाया जा सकता है।

लघु एवं कुटीर उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है और इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा करना भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए आत्महानन समान होगा लघु उद्योगों में श्रम के बाहर श्रम का उपयोग किया जाता है जबकि कुटीर उद्योगों में पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। एस०एस०आई० आधुनिक और पारम्परिक दोनों तकनीकों का उपयोग करता है जबकि कुटीर उद्योग उत्पादन और पारम्परिक तकनीकों पर निर्भर करते हैं।

लघु उद्योगों की श्रेणी में वे काम धन्धे आते हैं जिनमें मशीनों तथा पूँजी का अभाव व श्रम की प्रधानता रहती है। इसमें न बड़े बाजार की आवश्यकता होती है न ही अधिक कामगारों की घर के सदस्य तथा रिश्तेदारों के द्वारा यदि हम सेवा क्षेत्र में लघु उद्योग की निवेश सीमा की बात करें तो इसमें वे उद्योग शामिल किये जायेंगे जिनमें दस लाख से अधिक तथा दो करोड़ से कम का निवेश किया गया हो। इसमें भवन तथा जमीन आदि के खर्च को सम्मिलित नहीं किया जाता है।

भारत में निवेश सीमा को आधार बनाकर उद्योगों को सूक्ष्म/कुटीर, लघु और मध्यम उद्योगों की श्रेणी में विभाजित किया है। आम तौर पर लघु उद्योग हमारा आशय उन छोटे मोटे काम से है, जिन्हें कुछ लोग कम पूँजी के साथ शुरू कर सकते हैं, जैसे अपने घर पर, साबुन, अगरवत्ती, मोमवत्ती, कूलर, गुड आदि बनाना इसके अलावा पारम्परिक कार्य जैसे सुनारी, लोहारी, कुम्हारी, बढ़ई, पशुपालन, सिलाई, व कृषि कार्य को भी लघु उद्योगों की श्रेणी में सम्मिलित कर सकते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य –

भारत गाँवों का देश है तथा भारत में गाँवों का विकास उसकी अर्थव्यवस्था को बल देता है। अर्थात् गाँवों के विकास में देश का विकास निहित है और ग्राम्य विकास के लिए भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास अत्यन्त आवश्यक है। भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। इस अध्ययन के आधार पर भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थिति का तथ्यपरक विश्लेषण किया गया वर्तमान अध्ययन के आधार पर भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास के लिए आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं।



अध्ययन विधि :-

प्रस्तुत शोध आलेख रीवा जिले के लघु एवं कुटीर उद्योगों पर आधारित है जो मुख्य रूप से वर्णात्मक एवं विवेचनात्मक अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया है। शोध विषय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पारम्परिक कुटीर उद्योगों पर केन्द्रित है। लघु कुटीर उद्योग धन्धे स्व-श्रमशक्ति और स्वयं के श्रम पर फलीभूत होते हैं जो दैनिक निर्वहन के लिए जीवनोपयोगी वस्तुओं का निर्माण और आपस में विनिमय पर आधारित रहा है। अध्ययन में इस विषयवस्तु को वर्णात्मक पद्धति से विवेचित किया गया है।

लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से हम दैनिक आवश्यकता की सामग्री, लेखन सामग्री, सौन्दर्य व श्रृंगार उत्पाद, आयुर्वेदिक औषधि, प्रिंटिंग इंक, अगरवत्ती, आइस-क्रीम, डेरी उत्पाद, कन्फैक्शनरी का सामान, डिटरजेंट, प्लास्टिक वस्तुओं का उत्पादन, पेपर पिन, प्लास्टिक थैलियाँ, दियासलाई, खिलौने, विभिन्न प्रकार के मसाले, डबल रोटी, ड्राई सेल बैटरी, रेडीमेड कपड़े, विस्कुट, गुण, कपड़ों पर छपाई, नूडल्स, डिब्बा बन्द सब्जियाँ, मसाले, सॉसेज, पेंट आदि उत्पाद विभिन्न उद्योगों के द्वारा तैयार किये जाते हैं।

रीवा जिले में कुटीर उद्योग की स्थिति -

रीवा जिला गाँवों का जिला है। यहाँ पर कृषि के बाद ग्रामीणों के जीविकोपार्जन का साधन लघु एवं कुटीर उद्योग हैं। इन उद्योगों में परिवार के प्रत्येक व्यक्ति कार्य में लगे रहते हैं। लघु उद्योगों के लिये कम पूँजी, सीमित स्थान, कम कच्चा माल, कम उत्पादित वस्तुएँ, उत्पादन में हाँथ का अधिकाधिक प्रयोग, छोटी विपणन क्षेत्र एवं नवाचार आदि की कमी आदि विशेषताएँ होती हैं। इन उद्योगों का प्रशिक्षण परम्परागत ढंग से प्राप्त होता है, कोई भी संस्था प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था नहीं करती हैं। इन उद्योगों से निर्मित वस्तुएँ प्रायः हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली होती है। इनके निर्माण न होने से जीवन निर्वाह में कठिनाई हो सकती है।

सारणी क्रमांक-1 रीवा जिले में संचालित लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थिति

क्र.	उद्योग का नाम	प्रयुक्त कच्चा माल
1.	बांस की टोकरी उद्योग	बांस पर आधारित
2.	मिट्टी के बर्तन उद्योग	मिट्टी (दुमुट) का प्रयोग
3.	ईटा (भट्ठा) उद्योग	मिट्टी पर आधारित
4.	बीड़ी उद्योग	तेंदू पत्ता पर आधारित
5.	बढ़ईगीरी	लकड़ी पर आधारित
6.	लोहारगीरी	लौह तत्व पर आधारित
7.	सुनारी	सोना, चाँदी इत्यादि
8.	बरी एवं पापड़ उद्योग	बेसन एवं दाल
9.	दाल मिल	दाल पर आधारित
10.	चावल मिल	धान पर आधारित
11.	डेयरी उद्योग	दूध पर आधारित

12.	ब्रेड, बिस्कुट, सेवाइयाँ, नमकीन निर्माण	मैदा, बेसन, आटा पर आधारित
13.	चर्म उद्योग मांस व अण्डा उद्योग	चमड़े पर आधारित
14.	मांस व अण्डा उद्योग	मुर्गी, बकरे पर आधारित

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में प्रचुर मात्र में लघु एवं कुटीर उद्योग संचालित हैं। ये लघु उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर ये लोगों के जीविका दिलाने में उपयोगी है।

औद्योगिकीकरण के कारण इन उद्योगों में भी थोड़ा-बहुत मशीनीकरण का उपयोग होने लगा है तथा निर्मित वस्तुओं में निखार आने लगा, जिस कारण इन उद्योगों के प्रति समाज का आकर्षण कम नहीं हुआ है। यद्यपि वैज्ञानिक प्रगति के कारण कुछ वस्तुएँ कारखानों में बनने लगी हैं, जो आकर्षक एवं गुणवत्ता में श्रेष्ठ होती हैं जिन्हें लोग अधिक प्रयोग करने लगे हैं जैसे—जूट की रस्सी, बोरी की जगह पर प्लास्टिक की रस्सियाँ एवं बोरियाँ आदि। लकड़ी के जगह पर प्लास्टिक के समान आदि।

भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योगों की तुलना में कुटीर एवं लघु उद्योगों का बड़ा योगदान है। इसी क्षेत्र में अधिक रोजगार उत्पादन के अवसर पैदा किये हैं। आज भी हमारे लघु एवं कुटीर उद्योग वित्त समस्याओं से जूझ रहे हैं। यदि उन पर सरकार ध्यान दे तो निश्चय ही यह हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूत स्तम्भ की तरह कार्य करेगा, बड़े उद्योग देश के महानगरों तक ही सीमित है। कई मूलभूत समस्याओं जैसे बिजली, सड़क, तकनीक, कच्चे माल व बाजार की कमी के उपरान्त भी इस उद्योग क्षेत्र ने स्वयं के अस्तित्व को बनाये रखा है।

विकासशील देशों के आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में सबसे अधिक गाँव हैं। और ये लघु एवं कुटीर उद्योगों से जुड़ जाये तो देश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ का कार्य करेंगे। वर्तमान में भारतीय निर्यात का 34: हिस्सा इन्हीं उद्योगों से प्राप्त होता है। लघु उद्योगों ने बीते 50 साल में प्रगति के अनेक सोपान तय किये हैं। आर्थिक विकास में इन उद्योगों का योगदान अहम साबित हुआ है। तथा ग्रामीण इलाके में औद्योगिकीकरण का प्रकाश फैलाया है। जिसका प्रभाव ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पर देखा जा सकता है। अर्थात् ग्रामीण अर्थव्यवस्था दिन-प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है तथा गाँवों में नये-नये रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। अर्थात् भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत को गाँवों का देश कहा जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थात् कृषि से विभिन्न प्रकार के छोटे-बड़े उद्योग जुड़े रहते हैं। यदि भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास किया जाता है तो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो कृषि पर आधारित है और कृषि से अनेक छोटे-बड़े उद्योग जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से यदि इन छोटे बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी मजबूत होगी अधिक संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तथा ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा। अर्थात् उनके आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर में तेजी से सुधार होगा और ग्रामीण समाज निश्चित रूप में विकास के पथ पर तेजी से बढ़ेगा।

लघु एवं कुटीर उद्योग अपनी वस्तुओं का उत्पादन करके राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान देते हैं। यदि इनके तकनीकी स्तर पर सुधार किया जाये एवं बिजली से संचालित मशीनों के उपयोग की सुविधायें इन्हें प्रदान की जाये तो लघु उद्योगों की उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है और राष्ट्रीय उत्पादन में इनके और अधिक योगदान की आशा की जा सकती है।

हमारे देश में उत्पादन और राष्ट्रीय आय की वृद्धि में लघु व कुटीर उद्योगों का बहुत महत्व है। कुटीर उद्योग परम्परागत उद्योग है, इनमें कम पूँजी लगती है तथा घर के सदस्यों द्वारा ही वस्तुयें बना ली जाती हैं। लघु उद्योग में भी कम



पूँजी लगती है। लघु उद्योग इकाई ऐसा उद्योगिक उपक्रम है, जहाँ संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक न हो, किन्तु कुछ मद जैसे होजरी, हस्त-औजार दबाई व औषधि, लेखन सामग्री और खेलकूद सामान आदि में निवेश की सीमा 5 करोड़ रुपये तक है लघु उद्योग को नया नाम लघु उद्यम दिया गया है। सरकार अब इन उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध करा रही है और इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है तथा बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। लघु उद्योग छोटे पैमाने की वह उद्योगिक इकाईयाँ होती है, जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारम्भ करती है। इन इकाईयों में श्रम शक्ति की मात्रा भी कम होती है और सापेक्षिक रूप से वस्तु एवं सेवाओं का कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ये उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों से पूँजी की मात्रा रोजगार उत्पादन एवं प्रबन्ध, आगतों एवं निर्गतों के प्रवाह इत्यादि की दृष्टि से भिन्न प्रकार के होते हैं। रीवा जिले में इस परिप्रेक्ष्य में स्थापित लघु एवं कुटीर उद्योगों में पुरुष एवं महिलाओं की भागेदारी निम्नानुसार है—

सारणी क्रमांक-1. रीवा जिले के स्थापित लघु उद्योग तथा महिला पुरुष अनुपात

वर्ष	कुल पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या	पुरुषों द्वारा स्थापित संचालित लघु उद्योग	महिला द्वारा स्थापित/संचालित उद्योग	कुल स्थापित लघु उद्योगों में महिला उद्यमियों का प्रतिशत
2013-14	415	393	22	05.30
2014-15	454	434	20	04.60
2015-16	440	422	18	04.09
2016-17	448	427	21	04.69
2017-18	430	411	19	04.42
2018-19	402	391	11	02.76
2019-20	606	602	04	02.86
2020-21	553	537	16	02.86
2021-22	509	493	16	03.14
2022-23	203	475	28	05.57
योग	4760	4585	175	03.67

उक्त तालिका में रीवा जिले के स्थापित लघु उद्योग तथा महिला पुरुष अनुपात को दर्शाया गया है जिसमें वर्षवार कुल पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या 4760, पुरुषों द्वारा स्थापित संचालित लघु उद्योग 4585, महिला द्वारा स्थापित संचालित लघु उद्योग 175 तथा कुल स्थापित लघु उद्योगों में महिला उद्यमियों का 3.67 प्रतिशत है।

सारणी क्रमांक-2. जिला रीवा में पंजीकृत लघु एवं कुटीर उद्योग

वर्ष	स्थापित उद्योगों की संख्या	विनियोजित पूँजी (लाख में)	रोजगार संख्या
2017-18	454	255.21	895
2018-19	440	244.24	884
2019-20	448	248.35	815

2020-21	430	239.29	801
2021-22	478	322.78	543
योग 05 वर्ष	2250	1308.87	3938

उक्त तालिका के अनुसार रीवा जिले में वर्षवार पंजीकृत लघु एवं कुटीर उद्योग में से स्थापित उद्योगों की संख्या 2250, जिसमें विनियोजित पूंजी 1308.87 तथा कार्य करने वाले श्रमिकों को मिले रोजगार की संख्या 3938 है।

लघु एवं कुटीर उद्योग की समस्याएं –

वर्तमान समय में गाँवों की संरचना भी काफी बदल गई है और गाँवों में भी शहरों जैसी सुविधायें उपलब्ध हो गई हैं। जिससे बड़े-बड़े उद्योग स्थापित भी हो रहे हैं। अर्थात् छोटे-छोटे उद्योग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे हैं और धीरे-धीरे बन्द होने के कगार पर हैं। साथ ही ग्रामीण स्तर पर स्थापित लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल का अभाव रहता है और जो कच्चा माल उपलब्ध होता है वह परिवहन व्यय अधिक। कुटीर उद्योग धन्धों से अर्थ उन कुटीर उद्योगों से है जो पूर्णतया परिवार के सदस्यों की सहायता से आंशिक अथवा पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में कारीगरों के घरों पर ही चलाए जाते हैं। उद्योगों में विशेष पूंजी व श्रम की आवश्यकता नहीं होती। और ना ही इनमें कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है।

सुझाव :-

भारत की अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग के महत्वपूर्ण सुझाव निम्नानुसार प्रस्तुत है—

- कम पूंजी की आवश्यकता— भारत जैसे निर्धन देश में व्यक्तिगत व्यवसाय को चलाने के लिए कुटीर उद्योग ही उपयुक्त है। क्योंकि कुटीर उद्योग को चलाने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है।
- रोजगार की प्राप्ति— कुटीर उद्योग रोजगार के अवसर प्रदान करके बेरोजगारी की समस्या को हल करने में सहायक होते हैं।
- देश का संतुलित विकास—जिन क्षेत्रों में बड़े उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए जा सकते। तो उन क्षेत्र में कम पूंजी के द्वारा कुटीर उद्योगों का विकास करके देश का विकास किया जा सकता है।
- गाँव का विकास—गांव का सर्वांगीण विकास कुटीर उद्योगों में ही निहित होता है। ग्रामीण जनता बेरोजगारी से अधिक परेशान रहती है। इसलिए अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विकास हो जाए तो ग्रामीण जनता के समय का भी सही उपयोग हो जाएगा और उन्हें काम के बदले पैसे भी मिल पाएंगे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा
- वर्ग संघर्ष से बचाव—बड़े उद्योगों में मालिकों व श्रमिकों में संघर्ष बना रहता है। परंतु कुटीर उद्योगों में किसी भी प्रकार के वर्ग संघर्ष उत्पन्न होने का भय नहीं रहता है।
- अकाल के समय सुरक्षा—अधिकांश भारतीय जनता कृषि उत्पादन पर ही जीवन निर्वाह करती है अकाल के समय फसल नष्ट हो जाने पर कुटीर उद्योगों की सहायता से भरण पोषण किया जा सकता है।
- विदेशी मुद्रा का अर्जन—कुटीर उद्योगों में निर्मित कलात्मक वस्तुओं का निर्यात करके विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जा सकता है।



- कला कौशल की उन्नति—कुटीर उद्योग में हाथ से निर्मित वस्तुओं की प्रधानता रहती है। इसमें प्रत्येक कलाकार को कुटीर उद्योगों के माध्यम से अपनी पूर्ण क्षमता प्रदर्शित करने के अवसर मिलते हैं और उसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। प्राचीन काल में भारत के ढाका शहर की मलमल जो हाथ से निर्मित की जाती थी। विश्वविख्यात थी। इससे देश में कला कौशल की उन्नति होती है।

सन्दर्भ—

1. विकास अग्रवाल : लेटेस्ट प्राफीटेबल होम कॉटेज एण्ड स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज — हंस कान्सलटेन्सी ब्यूरो नई सड़क, दिल्ली।
2. गुप्ता, सुनील एवं चतुर्वेदी, राजीव : व्यावसायिक वातावरण एवं उद्यमिता, महावीर प्रकाशन, दिल्ली—2013
- 3- प्रो. शुक्ला, त्रिभुवन : उद्यमिता विकास, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, 2015
4. Behari, Bipin 1976, "Rural Industrialization in India" Vikash Publishing House, Pvt. Ltd.
5. Sarkar, Tamal (2009) Cluster and Cluster Development Yojana November 2009, Page 9
6. Venkatesh S. Muthiah. "SMEs in India: Importance and Contribution Asian Journal of Management Research 2012(2): 3-34
7. उद्योग व्यापार पत्रिका अगस्त 2012 इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई बिबपज
8. Krishnamohan, V. (2005) : "Challenges of Small Industry in the Past Liberalization Period", Financial Express, New delhi. Vol. 35 (91)
9. C. suryanaryan and V. Krishnamohan (ed) " Small Scale Industry Development in India. Social Science Press, New Delhi.

